

culated. We are not even aware that they could be introduced tomorrow also. Nothing has been indicated in the agenda paper today. We do not know how this Government is functioning. Everybody in the Government does not know what the right hand is doing. They are unable to see either hand. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: **Sush-maji, please.** (*Interruption*). For heaven's sake, let it not be that on every issue, every party has to make this. Mr. Mathur raised the question. I know your point of order. Please let me run this House. You will read some rule. I know already that it is a mistake. Every day, you want to raise a point of order. I allowed two people from your party. That is enough. (*Interruptions*). I have to say that, I am just trying (*Interruptions*)...

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): The Chair has accepted that it is a mistake. (*Interruptions*).

SHRI DIGVIJAY SINGH: Let the Government say this. (*Interruptions*).

SHRI AJIT P. K. JOGI: We are ruled by the Chair.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Why do we get angry over everything. Is it necessary? (*Interruptions*). It is neither the mistake of the Chair nor of the Secretariat. Let me put the record straight.

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): Then, this is the mistake of the Government. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think I have to stand up and then only, everybody will keep quite. (*Interruptions*). Mr. Swaminathan, you spoke enough.

SHRI G. SWAMINATHAN: It came along with the papers. The Minister did not send the paper directly. (*Interruptions*). The Secretariat should be responsible for this. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing. Please sit down. Unnecessarily, without knowing anything, the Members start having notions. If the Minister sends the papers, the Secretariat circulates them. It is asked first to list it in the business and technical mistake. The Minister should be asked first to list it then circulate these papers which is a requirement and the Parliamentary Affairs Minister should have been informed. The Rajya Sabha Secretariat and the Chair have nothing to do with it. That is all. (*Interruptions*). He has not come. There has to be a motion. (*Interruptions*). You don't have to tell me, I know that there has to be a motion. Whatever wrong has taken place has taken place. If he has to come, he has to come to withdraw it finally.

He has to come to the House and move a motion.

Demand for holding UPSC exams in 18 Regional languages of India

श्री विजय कुमार महोत्रा (दिल्ली): महोदया, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारे संविधान में 18 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएँ और भारतीय भाषाएँ कहा गया है। इनमें असमी, बंगला, तमिल, मलयालम, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, ये सब भाषाएँ हैं परन्तु आज संविधान बनने के 40 साल बाद भी, बल्कि 44 साल बाद यहाँ पर यू०पी०एस०सी० और लोक-सेवा आयोग की सभी परीक्षाएँ केवल अंग्रेजी भाषा में हो रही हैं। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता उसमें रखी गई है। इस बात की परमीशन नहीं दी गई है कि किसी अन्य भारतीय भाषा के माध्यम से ये परीक्षाएँ दी जा सकें।

उपसभापति महोदया, यह राष्ट्रीय शर्म की बात है, राष्ट्रीय लज्जा की बात है कि 8 साल से लगातार ये आंदोलन हो रहा है कि हमें तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, इन भाषाओं के माध्यम से भी ये परीक्षाएँ देने का अधिकार होना चाहिए परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इस बात को सबकावे के लिए धाबे पर

भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व उपराज्यपाल और बहुत से संसद सदस्यों को धरना देना पड़ रहा है।

महोदय, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यहां पर लोक सभा में 1990 में मैंने यह मंचाल जब उठाया था तो कांग्रेस पार्टी के साठे जी ने प्रस्ताव रखा और सारे सदन ने सर्वसम्मति से वह प्रस्ताव पारित किया जिसमें सभी दलों के लोग थे। जिसमें कांग्रेस के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, जनता दल के लोग थे, इन सभी दलों के लोग थे जिन्होंने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि लोक सेवा आयोग की सभी प्रतियोगिताएं सभी भाषाओं में होनी चाहिए। उसमें केवल अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। परंतु कुछ नौकरशाहों ने, कुछ लोगों ने या इस सरकार के सोते रहने से वह अंग्रेजी की अनिवार्यता आज तक चली आ रही है।

[उपसभाध्यक्ष (संचद सिद्धे रज्जी) पीठासीन हुए]

महोदय, इसके कारण केवल वे लोग जो अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से पढ़ते हैं, जो दून स्कूलों से पढ़कर आते हैं, जो स्विस् स्कूलों में पढ़ते हैं, जो इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ते हैं, वे केवल इस भाषा के माध्यम से बड़े-बड़े पदों पर आ जाते हैं। इसलिए नहीं आते कि वे योग्य हैं। इसलिए नहीं आते कि उनमें कोई प्रतिभा है बल्कि इसलिए आते हैं कि उनकी अंग्रेजी अच्छी है। इसलिए जो लोग भारतीय भाषाओं के स्कूलों में पढ़ते हैं या अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह पिछड़ जाते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, तीन प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं। उन्होंने अपना यह पकड़ना फंसा रखा है। उन्होंने सारे देश के शासन पर अपना वर्चस्व बना रखा है। उस के कारण भारतीय भाषाओं को सीखने वाले पिछड़ रहे हैं। इसलिए यू०पी०एस०सी० की परीक्षा के अंदर जिसके लिए सदन ने दो बार प्रस्ताव पारित किया, दो बार राष्ट्रपति ने अभ्यादेश निकाला, उस के बाद भी क्या

बात है कि वहां पर केवल अंग्रेजी भाषा में ही परीक्षाएं होती हैं। किसी भारतीय भाषा में परीक्षाएं नहीं देने दी जाती। आखिर कौन सी ताकत है जो कि उस को रखे हुए है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि कार्पोरेशन के स्कूलों में या गवर्नमेंट के स्कूलों में करोड़ों लोग जो अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं उन के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, उनका शोषण क्यों किया जा रहा है, गरीब मध्यम वर्ग के खिलाफ यह विषयासथात क्यों किया जा रहा है। इस अन्याय को समाप्त किया जाए और यू०पी०एस०सी० के अंदर अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करके सभी भारतीय भाषाओं को स्थान दिया जाए।

... (interruptions) ...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Let him complete. Mr. Swaminathan, I will give you the floor. Please take your seat. (Interruptions)... Mrs. Natrajan, I will give you an opportunity to ventilate your point of view. (Interruptions)... I will allow you.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH (Bihar): Don't worry. Please hear me first.

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो मामला प्रोफेसर मल्होत्रा जी ने उठाया है मैं कहना चाहता हूं कि उस को सदन में गंभीरता से लिया जाए। आज संघ लोक सेवा आयोग, यू०पी०एस०सी० के सामने भारतीय भाषाओं को लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मान्यता देने के लिए एक ऐतिहासिक धरना हो रहा है। मुझे याद नहीं है कि आज तक कोई ऐसा धरना या सत्याग्रह हुआ हो जिस में भारत के किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति ने, भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने भाग लिया हो। साथ ही साथ, विपक्षी दलों के नेता भी वहां मौजूद रहे। हमारे इस सदन के श्री चतुरानन मिश्र जी भी वहां शामिल थे। कुलविधुसिंह जो मणिपुर से आए हैं, वे भी शामिल थे। और भी कई लोग शामिल थे। इतना ही नहीं, महिला सांसद श्रीमती रेणुका चौधरी जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने भी इस के लिए

ब्लैसिंज भेजीं। कम से कम 60-70 दोनों सदनों के माननीय सदस्य वहाँ उपस्थित थे। यह मामला लोक सभा में और राज्य सभा में उठ चुका है। हमारे जो मित्र दक्षिण से आते हैं, उनको तकलीफ होती है और निश्चित रूप है तकलीफ होती है, लेकिन अगर मेरी बात से मेरे आचरण से उन को तकलीफ होती हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात उन को ध्यान से कहना चाहता हूँ, जयन्ती नटराजन जी भी सुन लें, कि मैं हिन्दी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। हिन्दी तो वहाँ पर है, अंग्रेजी भी है। हम सारे लोग जो कह रहे हैं वह सभी भारतीय भाषाओं के लिए कह रहे हैं चाहे वह तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, बंगला, काश्मिरी, पंजाबी, उड़िया, उर्दू, जो 15 भाषाएँ 1992-93 तक भारत के संविधान की अष्टम अनुसूची में है और उसके बाद तीन भाषाएँ, नेपाली, कोकणी और मणिपुरी उसमें और जुड़ी हैं। हमारा कहना यह है कि जब यू०पी० एस०सी० की परीक्षाएं पास करके सिविल सर्विस के परीक्षा पास करके कोई लड़का या लड़की जाती है, आइ०ए०एस० और आइ०पी०एन० बनकर, तो उसको संबद्ध राज्य में जाकर अंग्रेजी में नहीं बल्कि उस प्रांत की भाषा में काम करना होता है। तो यू०पी०एस०सी० में यह होना चाहिए कि कंपल्सरी अगर कुछ हो तो यह भारतीय भाषाएं कंपल्सरी बनानी चाहिए, अंग्रेजी को नहीं बनाना चाहिए।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): That is the problem.

श्री शंकर दयाल सिंह : इस के साथ ही मेरा कहना है कि हमारे जो दक्षिण भारत के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि, मैं हिन्दी की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, हिन्दी वहाँ है अंग्रेजी है... हिन्दी वहाँ है अंग्रेजी है लेकिन दूसरी भारतीय भाषाएं नहीं हैं। उनको स्थान मिलना चाहिये उपसभाध्यक्ष जी, इस संबंध में 1968 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था, दोनों सदनों के संकल्प पर और यू०पी० एस०सी० के सामने 88 संघटना अखिल भारतीय भाषा संरक्षण परिषद का कल

रहा है। दुनिया के इतिहास में 6-7 वर्षों तक...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Let him finish.

श्री शंकर दयाल सिंह : इस तरह का धरना नहीं हुआ होगा। जानी जैल सिंह जी वहाँ बैठे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बैठे हैं, देवीलाल जी बैठे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हैं, कांग्रेस के एक-दो माननीय सांसद बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन इसकी गंभीरता से ले और गृह मंत्री जी इस बारे में बयान दें। धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में भारत सरकार के गृह मंत्री जा आये और सदन में बयान दें कि क्या तक इस संबंध में फैसला लेंगे। यही मेरा कहना है कि आप उनसे कहिये कि तुरन्त कल तक सदन में उनकी तरफ से आश्वासन आना चाहिये।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SAYED SIBTEY RAZI): I will allow you. Shrimati Veena Verma (Interruptions)...

श्रीमती वीणा वर्मा (सध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष सदन में, मैं माननीय प्रो० मल्होत्रा जी और शंकर दयाल सिंह जी ने भारतीय भाषाओं को लागू करने का जो मुद्दा उठाया है, उससे अपने को सम्बद्ध करती हूँ। मैं यह कहना चाहूंगा कि 1990-91 में सतीश चन्द्र कमेटी को यह मैटर सौंपा गया था, तब से यह मैटर विचाराधीन है। संसदीय राजभाषा समिति अपने प्रतिवेदन का तीसरा खंड जब प्रस्तुत किया था तो उसमें यह सिफारिश की थी और यह कहा गया था कि भारतीय भाषाएं लागू हों और अगर अभी अगर भारतीय भाषाएं लागू नहीं हो सकें तो कम से कम विकल्प के रूप में हिन्दी माध्यम जरूर दिया जाना चाहिये। लेकिन तब से... (व्यवधान)...

चन्द्र कमेटी, जो वन में कमेटी है, वह अभी तक विचाराधीन है।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I will give you the floor. Please bear with me. (*Interruptions*)... The Deputy Chairman has already noted your name. So, let it be granted. Then I will give you the floor.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: No. I have no objection to Veenaji at all. I want to let her speak. What I want to say is... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please take your seat. (*Interruptions*)... Jayanthiji, please take your seat. I will allow you. When I am promising to give you the floor, why are you getting so agitated? (*Interruptions*)...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: You have not listened to me at all. (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Let us have her point of view first. Please sit down.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I am not objecting to Veenaji. You have not given me one minute. This is most unfair. I am not objecting to her. You don't listen to what I am saying.

श्रीमती वीणा वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमती आल्वा जी यहाँ बैठी हैं। उनसे निवेदन करूंगी कि 1990-91 में जो मतीश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट विचाराधीन है... (व्यवधान)...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, what is this?

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिन्ने रजी) : एनीज, कृपया... (व्यवधान)...

You will also be speaking. Please bear with her (*Interruptions*). All of you take your seats. I have permitted her. (*Interruptions*)...

श्रीमती वीणा वर्मा : संसदीय राज भाषा समिति.... (व्यवधान)....

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Why are all these Hindi people speaking together? We are not against Hindi.

SHRI DICVIJAY SINGH (Bihar): Who is speaking here about Hindi? (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्री सैयद सिन्ने रजी) : आप कृपया बैठिये।

श्रीमती वीणा वर्मा : उपसभाध्यक्ष महोदय, संसदीय राजभाषा कमेटी 30 सदस्यों वाली संसदीय समिति है। इस समिति ने जो अपना तीसरा प्रतिवेदन दिया—इस समिति में जो सदस्य हैं वे हर प्रांत और हर राज्य के हैं और उसमें यह सहमति ही यह विकल्प दिया जाय। तो वन में कमेटी पर क्यों इतना जोर दिया जा रहा है। कब तक यह सतीश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट पर विचार होता रहेगा और जो संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन का तीसरा खंड है उस पर कब कार्यवाही होगी? मैं माननीय मंत्री जी को, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि वे इन पर प्रकाश डालें।

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shrimati Jayanthi Natarajan.

SHRI G. SWAMINATHAN. Why don't you give an opportunity to the Opposition? Why are you giving the chance only to Congress Members?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I will give you the floor. I have noted your name. I will identify you.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Thank you very much for permitting me to speak, Sir. I associate myself whole-heartedly with what Professor Vijay Kumar Malhotra has said. I think the Indian languages should be given importance in the UPSC examinations. But I could not disagree more with what Shankar Dayalji said because this is the exact fear of the non-Hindi speaking people of the country. Under the guise that Indian languages should be promoted what Shankar Dayalji said was, "Please abolish compulsory English". (*Interruptions*)...

We are all aware of the rules. You already have the facility of taking the UPSC examination in the Hindi language and the English language. The demand is that it should be in all the national languages. I agree to it whole-heartedly. There is one compulsory English paper. My demand is that it should be retained. It is all very well for Shri Shankar Dayal Singh to say, "Scrap the English paper." (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please listen to her.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Pandit Nehru and successive Governments have given us the assurance that English language will be retained as a link language. Sir, people speaking different languages come to Delhi and participate in the Central Services. If they do not know Hindi, how do we communicate with them? Somebody speaks Assamese, very good. Somebody speaks Tamil, very good. How do Assamese and Tamilians communicate? This is a certain form of language fundamentalism. This imposition of Hindi through the backdoor will not be tolerated by the people of the South. The English language should be retained as a link language. The English language will always remain a link language. We will not allow you to force the Hindi language on us. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please sit down. (*Interruptions*) Please bear with me. Shri Muraoli Maran.

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): Sir, I am un-happy about the way in which the Hindi controversy is again raising its head. Yet, I am happy, that at least, the Tamil Nadu Congress people have learnt a lesson and they are preaching for the continuation of the English language. The ideal situation would be when all the 18 languages become the official languages. We should be able to take the UPSC examination in all the 18 languages. It would be an ideal situation. Our plea is that until and unless we are able to transact the nation's business in all the 18 languages, the English language should continue. There is no other way. The day if you jettison the English language, there will be danger to the unity of the nation (*Interruptions*).

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Not at all... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I will allow you. (*Interruptions*). Don't be so emotional. (*Interruptions*). It is a very sensitive issue. Mr. Muraoli Maran is speaking. Let him complete. (*Interruptions*). Let him complete.

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, the English language is not my mother tongue. I have no love or affection for the English language. But the English language is a must. It is a necessary. Once Pandit Nehru said, "English is a window to the world." If you close the English language, then we will be ignored. It is an international language. It is not a colonial language. The situation is not like that. Almost all the countries in the world are now learning the English language. Even the French people who are very affectionate towards their language, are also learning the English language. Therefore, I would say, "Let us not be hasty." Let us not... (*Interruptions*). The English language a boon of Saraswati. Let us not abandon it. If you abandon it, how will we understand one another. It is the only link which is available. Until and unless we attain a situation where all the 18 languages become the

official languages, the English language should continue. Let us not be so hasty. If you become hasty, then the unity of the nation will be in danger. You are jeopardising the unity of the country.

SHRI G. SWAMINATHAN: I am very happy that hon. Members Shrimati Veer Verma, Shri Shankar Dayal Singh and Prof. Malhotra are advocating for the regional languages. We all agree that the regional languages should find a place in the administration of the country. There is no doubt about it: But then we, who are coming from the South, are finding it extremely difficult, except that in Parliament, when we speak, our speech is translated. But, in Question Hour, our people from the South are finding it extremely difficult. If you do not know English, then whatever interpellation you make in the question Hour will not be understood. (*Interruptions*). I am only expressing my feelings. It is because I know English that I am able to interpellate in that language. But there are many Members, in my party itself, who are very good speakers but who are not able to interpellate properly in English during the Question Hour and there is no simultaneous translation at that time. If that is the position in Parliament, you can understand the plight of the people who come over here and who do not know Hindi. When I speak to a telephone operator in English, she replies in Hindi. Even if you have to get a ticket at the railway station, when you speak to the clerk in English, he does not speak in English but he speaks in Hindi only. I had a feeling that they were deliberately doing it. But, when I happen to talk to some people there, they said that they knew Hindi only and that they didn't know English. The situation that has come about in the North is that even though there should be a two-language formula, most of the Hindi-speaking States are now going in for a one-language formula. We have seen the case of Bihar and we also note that in Uttar Pradesh, English has now been relegated to the third place and it is also not compulsory. What they are trying to do is

to relegate it further so that the people in the North need not know English. If they do not know English, the people in the South, who may know English only, will not be able to communicate with these people. With all respects to Mr. Shankar Dayal Singh, I would like to say that while he is advocating the prominence and importance of the regional languages, I feel that when you jettison English, there will, then, be no linkage between the South and the North. Sir, I, as one who is interested in the congress people, interested in this Government, interested in everything, would only say that when there is a fissiparous tendency prevailing all over the world—even big countries are unnecessarily breaking up and they are getting into a lot of difficulties—we are very happy that India is united even though we have many problems today, whether economic or any other thing. I would request my friends, "Don't try to create a monster at this stage." Madam, at this stage, I want to point out the feelings among the people in the South. I am one who is personally very compromising and our hon. Chief Minister herself knows Hindi. With all that, when you start talking like this, my blood boils. People in the South feel that they are being pushed into the wrong side. As I have already said, you are jettisoning the unity of the country. You are jeopardising the very unity of the country, more so when the unity of the country should be uppermost in our minds. I would request the hon. Members to give due importance to the regional languages...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Now, please conclude... (*Interruptions*). I would request you to conclude.

SHRI G. SWAMINATHAN: Don't create disunity in the country.

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Sir, I also want to add something, with your permission... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Shri Chaturanan Mishra,

विक्ष के नेता (श्री सिकन्दर जस्त) :
सदर साद्विवा मैंने भी गुजरिश की है।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, लैंग्वेज का सवाल अपने देश में कितना कम्प्लिकेटेड है यह तो इस सदन की बहस में ही पता चलता है। इतने आदमी बैठे हैं और उनमें इतना सेंसिटिव क्वेश्चन यह है इसलिए इसको हम लोगों को गंभीरता से लेना चाहिये। अगर कोई आदमी यह कहता है कि हिन्दी ही एकमात्र आफिशियल भाषा हो इसके लिये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि आफिशियल लैंग्वेज है लेकिन उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि—

Notwithstanding English to continue for official purposes.

और इसी के मामले में हमारे उस वक्त के प्रधान मंत्री नेहरू जी ने लिखित वादा दे दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज कंटीयु करेगी फार आफिशियल परपजज। मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है जो उन्होंने वादा किया था उसे हम लोग वापस लें, दैट शुड नाट बी डन।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: (Tamil Nadu): Nehru's assurances have not been put into effect... (Interruptions) Over the last 40 years, they have failed to implement them.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I referred to that also.

1.00 p.m.

That stands. What is the issue at present? On this, I am of the opinion that the Hindi language should not be imposed on non-Hindi-speaking people. Similarly, the non-Hindi-speaking people should also not impose English on the Hindi-speaking people... (Interruptions)...

SHRI J. S. RAJU (Tamil Nadu): We are not imposing... (Interruptions)...

is only a hind language... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I request the hon. Members to bear with me. Members have to listen to the point of view of others also. I request all of you to take your seats. Please take your seats. You have to listen to the point of view of others. You cannot do like this... (Interruptions)

SHRI CHATURANAN MISHRA: Please listen to me. When I am speaking, why are you interrupting?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Mishra... (Interruptions)... Mr. Mishra... (Interruptions). Mr. Chaturanan Mishra, please address the Chair. You please don't involve yourself in cross-talk... (Interruptions)... Please take your seats. I had already given you the floor. You have to listen to the point of view of others also. Democracy requires us to hear the point of view also. You cannot bulldoze like this. You please take your seats... (Interruptions)... I am sorry. You please take your seats. I have given the floor to all of you. It is not fair. You have to listen to the point of view of others. Please take your seats. If you want to say something, if you want to differ from him, I will give you the floor again. But please don't disrupt the proceedings of the House like this. No, I am not permitting I am not allowing this. The Chair is on his feet.

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, one minute... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Maran, you are a very senior Member. I am sorry to remind you this. Please take your seat. This is not fair. You have to hear the point of view of others also. This is what democracy teaches us. You please take your seat... (Interruptions)... Mr. Murasoli Maran, you are a senior Member. How can I convince you? If you want to say something, I will allow

you later on. I am not going to permit you like this... (Interruptions)... Mr. Mishra, you please finish.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Let me finish. I will come to all your questions. If you want to put any question, I will answer it. I want to complete my version.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: This is the plight of the South Indians (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED-SIBTEY RAZI): I am sorry that this is no a question of South India. This is a question involving our nation. You should think of everything in that perspective. I am sorry that you are passing such remarks. I am not going to permit such things. I am not going to give you the floor like this.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I have already said that the assurance given by Pandit Jawaharlal Nehru should remain.

SHRI MURASOLI MARAN: What is the assurance?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED-SIBTEY RAZI): Mr. Mishra please try to be brief and make your point of view. This is not a debate. This is not a discussion at all.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Mr. Vice-Chairman, I would have finished my speech by this time. I have already pointed out that whatever assurance was given, it must remain. Neither should the non-Hindi-speaking people impose English on the Hindi-speaking people nor should the Hindi-speaking people impose Hindi on the non-Hindi-speaking people.

SHRI MURASOLI MARAN: That is where he is twisting the issue... (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED-SIBTEY RAZI): Why don't you allow him to speak?

SHRI MURASOLI MARAN: Nehru's assurance is that English will continue as long as the non-Hindi people want it. There is no question of imposing it.

SHRI CHATURANAN MISHRA: How is it being done? In the UPSC examinations, there are certain papers in which people are forced to write in English. It is on record. There are certain papers in which the questions are in English and people are asked to write in English alone. This is compulsory.

SHRI MURASOLI MARAN: There is only one paper.

SHRI CHATURANAN MISHRA: No, not one paper.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED-SIBTEY RAZI): Mr. Mishra, please try to conclude... (Interruptions)... I will permit you... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (संयद सिब्ते रजी)
कृपया समाप्त करें क्योंकि और लोग भी हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : हम को समाप्त तो करने दें, हम तो समाप्त कर रहे हैं।

Therefore, what we are saying is... (Interruptions)... Just a minute. Therefore, today's dharna is not to make Hindi compulsory. Nothing of the sort.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: From backdoor.

SHRI CHATURANAN MISHRA: No backdoor. How can the question be through backdoor? (Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (संयद सिब्ते रजी) :
चतुरानन जी, आप अपनी बात कह दें। बीच बीच में इंटरप्स का जवाब न दें आप अपनी बात कह दें चतुरानन जी।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: In the name of Option, Hindi is being imposed on the South Indians.

SHRI CHATURANAN MISHRA:
If that is happening in South India, if that is so, why don't you go in 'dharna'?

SHRI G. SWAMINATHAN. We will go in 'dharna'.

SHRI CHATURANAN MISHRA:
If you want, I will support you.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:
In practice, Hindi is being imposed.
(Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (संयद सिन्हे रजो) :
चतुरानन जी, आप हमसे बात करें, चेयर से बात करें। उनको भूल जाइए। उनके बारे में चिंता मत कीजिये। मैं उनको देख रहा हूँ। आप अपनी बात कहिये।

श्री चतुरानन मिश्र : हम अपनी ही बात कहना चाहते हैं। आगे से कहेंगे तब न, पीछे से कोई कहेगा तो कैसे होगा? महोदय, हम बताना चाहते हैं कि आज का धरना इस बात के लिये नहीं है जैसा कि वह लोग कह रहे हैं। सिपल बात यह है कि हिन्दी जानने वाले या दूसरी भाषा के जानने वाले चाहते हैं कि जहाँ पर इंगलिश कंपलसरी है, वह कंपलसरी न हो। अगर एक पेपर आप रखना चाहेंगे इंगलिश का भी तो होगा, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि इंगलिश की स्थिति बदल गयी है। हमारी नाथ ईस्ट की कुछ स्टेट्स ने इंगलिश को एडाप्ट कर लिया है।

उपसभाध्यक्ष (संयद सिन्हे रजो) : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री चतुरानन मिश्र : रीजनल लैंग्वेज का जो प्रोब्लिम था, उसको एडाप्ट कर लिया है और हम उनके प्रति भी भावुकता से नहीं जाना चाहते हैं और न मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के बारे में यदि कोई बात करता है, तो वह गुलामी की बात करता है या दलाल है। इस सब के हम सब्त खिलाफ है, लेकिन हमने आपसे साफ-साफ कह दिया है कि दो बात स्पष्ट होनी चाहिये कि न हम आपको हिन्दी लादेंगे और न आप हम पर अंग्रेजी लादिये।

उपसभाध्यक्ष (संयद सिन्हे रजो) :
श्री जयपाल रेड्डी।

श्री चतुरानन मिश्र : दोनों मिलकर देश को आगे ले जायें और इसीलिये मैं अपना सुझाव देता हूँ कि प्रधानमन्त्री को अविनंश तमाम चीक निनिस्टर को मीटिंग, पालिटिकल पार्टीज की मीटिंग बुलानी चाहिये क्योंकि साउथ के लोग भी एजीटेड हैं, हिन्दी वाले भी एजीटेड हैं। ऐसे वक्त में लीडरशिप को फेन नहीं करना चाहिये और कोई रास्ता निकालना चाहिये।

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am from South India. But I did not find any contradiction between the position taken by Prof. Malhotra, Shankar Dayal Singhji and others and the position taken by Mrs. Jayanthi Natrajan, Shri Murasoli Maran and Shri Swaminathan. I did not find any contradiction. My powers of understanding may be, perhaps, limited. The question today is very limited.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH:
I do not agree. It is unlimited.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The question today is very limited. The UPSC should take care of the regional languages. There is no need to pit regional languages or Hindi against English.
(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mrs. Alva, if you want to intervene just now, I can give you the floor.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): I have to go to the other House also. They are calling me because of the same thing....

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I got your name. But you said that you will speak at the end.

SHRIMATI MARGARET ALVA:
Let me clarify and go.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): There are two more Members who want to speak. If you want to intervene just now, I can ask Mr. Reddy to sit down, and you can intervene.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I will speak later.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): She has to go to the other House. Let her take the floor.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, there are a few points which have been raised, and we are also aware of the agitation that has been referred to. I would like to make one or two issues clear so that, probably, a lot of confusion which has been created could be sorted out. Eight years ago, for what is known as the Civil Services Examination which covers 27 Services, all the languages of the Eighth Schedule were introduced. You can take the examination in any of these languages what is known as the Civil Services Examination. Since the last eight years, this facility is available. This facility is available ... (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Let her complete. I request you. Let her complete her statement.

SHRIMATI MARGARET ALVA: This is the Combined Civil Services Examination which covers 27 services like the IAS, the IPS, the Foreign Service. There are 27 Services. Besides this, there are other examinations also. For instance, for the Engineering Services, since most of the technical terms are in English, it is still conducted in English because everybody in the country is not able to switch over to all these languages for technical services. But there is a demand, and I concede there is a demand, that every examination that is being conducted should be conducted in other languages. I would say without hesitation that the Satish

Chandra Committee which has been mentioned has made recommendations. We are in the process of switching over. I cannot say in one day because it takes a certain process to conduct these examinations in so many languages. I assure you that none of us is against all the languages being given an equal place in conducting Civil Services Examinations. Give me a little time. I cannot here go through the details of where and how we are processing it; but we are in the process of implementing the recommendations of the Satish Chandra Committee. But there is a second issue on which I would admit. I come from the South. I am not anti-Hindi. I had Hindi as second language for my B. A. Coming from the South, I am not taking a position on this. I am saying that English paper is still there as a compulsory paper. But let me clarify it. It is 10+2 level for the Civil Services Examination and it is a qualifying exam. Marks are not added for ranking. So, the rank is not affected whether you get 60 marks or you get qualifying 30 or 35 marks. Please realise that for the present, as long as so much of the work of the Union Government is taking place in English not because we chose it but because we had 200 years of British rule due to which all the records and files are still in English—we have to, for the present, without cutting the link of being able to communicate with each other in the country, use English up to a point. We have Hindi Salahkar Samitis. We have them in the Ministries. We are trying to bring in typewriters, train people both in English and in Hindi, and so on.

SHRI SIKANDER BAKHAT: I want you to yield for half a minute. Has somebody from the Government gone to that place of dharna and given this sort of an assurance?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am sorry. I am very clear that these issues cannot be settled by the roadside or in dharnas. I am very sorry.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Not today, but for eight years

it has been there. Satish Chandra Committee report is there for the last four years.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Mr. Malhotra, you have reports of various committees and your own Poll Reforms committee's reports are lying. Have you been able to come to a conclusion within one year or half a year? You have to carry all the States with you, I am sorry. This is not a question which concerns... (Interruptions). I

am sorry. On every question of examination reforms—because they are All India Services in which all the States are participating—I have to—and it is required of us to—consult all those involved, and I can assure you that the process has been gone through, a consensus has emerged and the issue is in the final stages of implementation. But I would certainly say even today that we are not considering abolishing the English paper because the assurance has been given that link language will continue and we stand by it.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Mr. Vice-Chairman, I had not completed.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I think the matter ends. The Government has made the position clear. You have been able to draw the attention of the Government to the dharna. Do you still want to say something? She has clarified the stand of the Government. Mr. Jaipal Reddy, I will give you just two minutes.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, today, we allowed language to become a bone of contention. The dharna is limited to the question of accelerating the process of introduction of regional languages as the media of examination. There is no question... (Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA: In other exams, it is there. (Interruptions).

SHRI S. JAIPAL REDDY: I am not reacting to what the hon. Minister has said. I am only trying to moderate what had been talked about earlier.

SHRIMATI MARGARET ALVA: What is there to discuss?

SHRI S. JAIPAL REDDY: There is no need to pit the regional languages against English. English shall continue. Hindi shall continue. In addition to these two, the regional languages of the country should also be strengthened. That is the idea.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I think that is enough. (Interruptions)

SHRI SIKANDER BAKHT: Please.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Sir, I will take just half-a-minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): The Leader of the Opposition is on his legs. I have identified him. (Interruptions)

If all Members are very anxious to make their point of view at this stage, it is okay. But this is not a discussion. It has been allowed just as an item in the Zero Hour.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, Mr. Jaipal Reddy himself did not understand what he was talking about.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTEY RAZI): Sikander Bakht, please.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, मैं एक वृत्त ही सुखतिर बात अर्ज करूंगा।
.. (व्यवधान) ..

श्री अजीत जोगी : (मध्य प्रदेश) :
आपने उधर से भी सुना, इधर से भी सुना, मध्य में नहीं सुना, हमको भी सुन लीजिये।

उपसभाध्यक्ष : श्रीसैयद सिद्दीक़ुल्लाह :
आप को भी सुनेंगे,

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, जो जवान मैं बोलता हूँ, उसे उर्दू कहा जाता है, बदकिस्मती यह है कि जयपाल रेड्डी साहब

साहब, जो बात कहीं है, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ कि मल्होत्रासाहब ने और शंकर दयाल सिंह जी ने गजो बात उठाई है, वह इतनी मुश्तसिर थी कि उसके लिये इतने जुमले, इस किस्म के खास तौर से पार्लियामेंटरी मिनस्टर साहिबा की तरफ से भी आये, व खतर नाक हैं, नहीं आने चाहिये थे। बात सिर्फ इतनी मुश्तसिर सी है कि अंग्रेजी को अपनी जगह कायम रहना चाहिये, कोई अंग्रेजी की मुखालिफत नहीं कर रहा, कोई हिन्दी की इक्वीजीशन की बात नहीं रहा, हिन्दी और अंग्रेजी के साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेज जितनी भी 8वें शैड्यूल में हैं, उनमें भी इम्तिहान में बैठकर जवाब देने की इजाजत होनी चाहिये। यह जो बदकिस्मती से भाषा के रकावत के सवालालत यहां कह जाते हैं और खास तौर से जिम्मेदार लोग जब कहते हैं तो बड़ा दुख होता है। अभी मार्टिनाइजेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जयपाल रेड्डी साहब ने और बिल्कुल दुरुस्त है कि व्यामबाह तोड़-मरोड़कर किसी एक जवान को दूसरी जवान के मुकाबले में लाकर खड़ी करने की खुदा के वास्ते कोशिश मत कीजिये। कोई अंग्रेजी को हटाने की बात नहीं कर रहा, कोई हिन्दी को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा, वे कह रहे हैं अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ हिन्दुस्तान की तमाम वे जुबानें, जो 8वें शैड्यूल में हैं, उनमें भी इम्तिहान में जवाब देने की इजाजत होनी चाहिये। उसके बाद यह इट्रोड्यूस करना, कोई हिन्दुस्तान की यूनिटी को खतरा है, मेरा ख्याल है कि इस एटी-च्यूट से ज्यादा बेहतर हिन्दुस्तान की यूनिटी के लिये दूसरा एटीच्यूट हो सकता है नहीं कि हमारे लिये तमाम भाषायें, अंग्रेजी समेत, मान्य हों। मुखालिफत किस बात की है? मुश्तसिर बात है और उसके बीच-बीच में यह जुमले कहना कि हमारे ये प्रांत भी हैं, हमारी ये भाषायें हैं, सही नहीं है। मैं उर्दू वाला हूँ, उर्दू पर जान देता हूँ, लेकिन उर्दू के सवाल को सियासी मन्च पर लाना मैं उर्दू के खिलाफ गुनाह मानता हूँ सब जवान हमारी हैं, आखिर हम यह जहन क्यों नहीं बना सकते? अगर हमको हिन्दुस्तान की

एकता से इतनी दिलचस्पी है तो हम सब जवानों को ईमानदारी से अपनी भाषा क्यों नहीं मान सकते, हम उनका एहताराम क्यों नहीं कर सकते? क्षमा करें, सवालालत को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। अंग्रेजी को कोई मुखोलिफत नहीं है, लेकिन हिन्दुस्तान की तमाम भाषाओं का एहताराम करते हुये उनमें भी जवाब दिये जायें, इसकी बात होनी चाहिये।

شمس الدین بخت: صدر صاحب
جو زبان میں پڑتا ہوں اسے اوروکھا
جاتا ہے۔ بدقسمتی سے کہ جب پل پڑتی
صاحب نے جو بات کہی ہے۔ میں اس کو
دہرانا چاہتا ہوں کہ ملہوترہ صاحب
نے اور شکر دیال سنگھ جی نے جو بات
اٹھائی ہے۔ وہ اتنی مختصر تھی کہ اس سے
لے کر اتنے جملے اس قسم کے بنائے گئے
سے پالینٹری منسٹر صاحب کی رائے سے
بھی آئے۔ وہ خطرناک ہیں۔ انہیں آتے
چاہیے تھے۔ بات صرف اتنی مختصر
ہے کہ انگریزی کو اپنی جگہ قائم رہنا چاہیے
کوئی انگریزی کی مخالفت نہیں کر رہا۔
کوئی ہندی کی امیدواریں کی بات نہیں
کر رہا۔ ہندی اور انگریزی کے ساتھ
ہی ساتھ ریجنل لینگویج جتنی بھی آٹھوں
شٹیڈول میں ہیں۔ ان میں بھی امتحان میں
بیٹھ کر جواب دینے کی اجازت ہونی چاہیے
یہ جو بدقسمتی سے بھاشاکے رقابت
کے سوالات یہاں پر کہہ جاتے ہیں۔ اور

خاص طور سے ذمہ دار لوگ سب کہتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ابھی مارڈز ناٹکیشن کا لفظ استعمال کیا۔ جسے بال ریڈیو صاحت سے اور بالکل درست ہے کہ شہزادہ پنجاہ آٹھ سو کو کس کی ایک زبان کو دوسری زبان کے تھیلے میں لاکھ کھڑی کرتے کی غذا کے واسطے شیشتر سے کھینچتے کوئی انگریز کرپشنلے کی بات نہیں کہہ کر کوئی ہندی کو کہتا ہے کہ بات نہیں کہہ کر۔ وہ کہہ رہے ہیں انگریز اور ہندی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی تمام زبانیں ہندو آٹھ سو شیشتر میں ہیں۔ اس میں بھی استحقاق میں جواب دہ کی اجازت ہوئی چاہیے۔ اس کے بعد اسے انگریزوں کے زنا کوئی ہندوستان کے لیے کو خطرہ ہے میرا خیال ہے کہ اس لیے میں سے زیادہ بہتر ہندوستان کی یونٹ کیلئے دوسرا ایٹمی ٹیوٹ ہو سکتا ہے نہیں کہ ہمارے لئے تمام بھاشا میں۔ انگریزی سمیت ماننے ہوں۔ مخالفت کس بات کی ہے۔ مختصر بات ہے اور اس کے بیچ میں یہ جملہ کہنا کہ ہمارے یہ پرائنٹ بھی ہیں۔ ہماری یہ بھاشا میں ہیں۔ صحیح نہیں ہے۔ میں اُردو والا ہوں۔ اُردو پر جان دیتا ہوں۔ لیکن اُردو کے سوال کو سیاہی منچ پر لانا میں اُردو کے خلاف گناہ مانتا ہوں۔ سب زبانیں ہماری

ہیں۔ آخر ہم یہ ذہن کیوں نہیں بنا سکتے اگر ہم کہ ہندوستان کی ایکتا سے اتنی عجیب ہے تو ہم سب زبانوں کو ایک انداز سے اپنی بھاشا کیوں نہیں مان سکتے۔ ہم ان کا احترام کیوں نہیں کر سکتے۔ اکٹھا کریں۔ سوالات کو توڑنے مروڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ انگریزی کی کوئی مخالفت نہیں ہے۔ لیکن ہندوستان کی تمام بھاشاؤں کا احترام کرتے ہوئے ان میں بھی جواب دینے سے باز نہیں۔ اس کی بات ہوئی چاہیے۔

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIB TEY RAZI): Mr. Hanumanthappa.. (Interruptions).

Mrs. Jayanthi Natarajan, please take your seat. (Interruptions)

श्री सिकन्दर बख्त : आपकी प्रवाज मेरे खानों में सगीत बनकर जाती है, इसलिये मैं सुन नहीं सकता तो मुझे तकलीफ होती है। कहिये तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। ... (व्यवधान)

شری سکندر بخت : آپ کی آواز میرے کانوں میں سنگیت بن کر جاتی ہے اس لئے میں سن نہیں سکتا تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ ... مداخلت۔

THE VICE-CHAIRMAN: Mr. Hanumanthappa, please. (Interruptions) All of you, please take your seat. (Interruptions)

SHRI S. MUTHU MANI: For regional languages, there is no typewriter facility in the Rajya Sabha. (Interruptions).

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): (Spoken in Kannada)... (Interruptions).

उपसमाध्यक्ष महोदय, बड़े दुखी दिल से मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आपस के सारे भारत के लोग आपस में कैसे लड़ रहे हैं। क्या हम लड़ने के लिये इधर आये हैं? लड़ने के लिये हमने आजादी को लिया है? इतने सालों के बाद भी हम आपस में लड़ रहे हैं यह भाषाओं को लेकर, यह सोचना चाहिये। आप अपने दिल खोलकर सोचिये।

The problem is, some of you speak Hindi, some others do not understand that at all... (Interruptions)... Just a minute,

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: Some people do not understand English... (Interruptions)...

SHRI S. MUTHUMANI: The country has to go forward... (Interruptions)... Then only we can understand and have our rights.
... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Please take your seat.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Some people who talk in Tamil just like Mrs. Jayanthi Natarajan, or some people who talk in Kannada, like Hanumanthappa, are not understood by the Hindi-speaking people. So, we have to find a way out. The founding fathers of our Constitution gave us something and we have accepted the three-language formula. How long do we protest? Why are you fighting today? It is not because of language. It is because of sharing of services. That is more important. Why are you on *dharna* today before the UPSC and not at the door of Parliament House? You have gone to the UPSC because it is a question of sharing of posts... (Interruptions)... This is the crux of the problem. It is not a question of the language of Tamil, Hindi, Assamese or Kannada... (Interruptions)... It is the sharing of jobs. Come, let us accept it today, let us split the services according to States on *inter se* merit. You take on *inter se* merit, we take on *inter se* merit, let

the North-East take on *inter se* merit, let Assam take on *inter se* merit. Then there is no question of *dharna* before the UPSC. This is the real problem, not language. When I go out, if want a cup of tea,

किसी भी तरह से हम मनेज कर लेते हैं अगर भाषा भी नहीं चाहिए आप भी तमिलनाडु में गए हैं होटल में गए हैं कहते हैं जाकर के कि यह क्या है। यह ही जिक्र है क्या

Even by signs we are able to do it. So it is not a question of language. It is a question of sharing of resources, sharing of services, sharing of administration. This is the problem here... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Prof. Dutta... (Interruptions)... Now you listen to the hon. Member from the North-East.

SHRI H. HANUMANTHAPPA.: How honest are we? I am not against any regional language, I am not against Hindi... (Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Mr. Hanumanthappa. I thought you have completed.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I can understand Hindi, I can speak Hindi, I can speak Kannada also. But how fair are you to the country?

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): I have identified another Member.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Let us not quarrel on languages. There are basic issues yet to be decided. Let us think on those lines. The whole country is watching what we are doing here. This is not the way.

DR. B. B. DUTTA (Nominated): Sir, what we are afraid of is this, there is a trend—in this discussion also it was quite evident—to downgrade English, to slowly corner English and give Hindi an increasingly upper hand. This kind of a manipulation will create a danger for the nation.

See what the picture in the North-East is. We have got so many North-Eastern States. Their State language is

English. And the numerous tribal communities are using English as their link language. In the State Assemblies, the entire deliberations of those Assemblies are being conducted in English. Those States are demanding inclusion of English in the Eighth Schedule itself. I must inform the House that English, after the British had left India, is no longer a foreign language. It is an Indian language. Some of the brightest sons and daughters of this country have written in English. You see the publications. Beautiful English literature has come up from the Indians, not from the Englishmen. English medium schools are multiplying and spreading into interior areas. We should not forget all these things. We should not take a myopic view of India. Our vision of India, should be about India as it is, not of a truncated India, not merely a part of it, the Northern India, the Southern India or the Eastern India. We should have a clear vision of the country. For God's sake, don't bring in this issue. We have the highest respect for all the eminent leaders sitting there. We have the highest regard for Hindi. We understand Hindi easily... (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN (SYED-SIBTEY RAZI): All right. Try to be brief.

DR. B. B. DUTTA: Don't try to push... (Interruptions).

THE VICE-CHAIRMAN: It is not a discussion... (Interruptions).

SHRI DIGVIJAY SINGH (Bihar): Mrs. Alva you should go to the Lok Sabha. Why are you sitting here?... (Interruptions)

मार्ग्रेट अल्वा जी को तो लोक सभा में जाना था, ये यहां बैठी हुई हैं। उस समय तो हम लोगों के बोलने पर आपने कहा कि इनको लोक सभा में जाना है। अब ये नहीं रहेंगी ?

श्री शंकर दयाल सिंह : आपको सुनने के लिए बैठी हैं तो आप खुश होइये।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं इस बात को मामला हूं कि देश में पहले

ही बहुत समस्याएँ मौजूद हैं। इसलिये ऐसा कोई सवाल उठाने का मेरा मतलब नहीं है जिससे तनाव बढ़े। मैं शुरू में ही यह बात कहना चाहता हूँ लेकिन जिन लोगों ने इस सवाल को उठाया था, विजय कुमार मल्होत्रा और शंकर दयाल सिंह जी ने, उसका एक बड़ा ही सीमित दायरा था कि भारतीय भाषाओं का सम्मान हर जगह इन परीक्षाओं में होना चाहिये। रीजनल लैक्वेजेज का भी होना चाहिये। अंग्रेजी अपनी जगह पर है, हिन्दी पहले से वहाँ पर है। न ये अंग्रेजी का मामला है, न ये हिन्दी का मामला है। यह तो जिन लोगों की आस्था है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न हिन्दी जानें न अंग्रेजी जानें, उनके लिये है कि वे अपनी रीजनल भाषाओं में भी अपनी बातों को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इसलिये हम इम्तहान में इनको यह सुविधा दी जाय। इसका अलावा इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन जहाँ माहौल इस तरह से बरकत दिया गया जैसे कोई अंग्रेजी, हिन्दी पर धोपना चाहता है, अंग्रेजी नहीं रहेगी तो यह देश नहीं चलेगा (व्यवधान) 5,000 साल की सभ्यता है इस देश की। अंग्रेजी 200 साल पहले इन देश में आई है। पाँच हजार से यह देश बन रहा है बिना अंग्रेजी भाषा के... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SYED-SIBTEY RAZI): No., no. Please. (Interruptions)... Please, Mr. Virumbi, Mr. Virumbi, please take your seat. Don't be excited.

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, हमें यह तो मालूम हो जाय कि खफा किस बात पर है ? किरा बात से खफा हैं मालूम हो जाये तो हम छोड़ देंगे... (व्यवधान)

شری سیکندر بخت : صدر صاحب۔
ہمیں یہ تو معلوم ہو جائے کہ خفا کس
بات پر ہیں۔ کس بات سے خفا ہیں۔ معلوم
ہو جائے تو ہم چھوڑ دیں گے۔۔۔ (بلاخلافت)

श्री दिग्विजय सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, सिकन्दर बख्त साहब ने बिल्कुल सही बात कही। उर्दू इस देश की जंग-ए-आजादी की भाषा थी। कहां की आप बात कर रहे हैं? आजादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने लोग हिन्दी जानते थे, वे उर्दू में अपने भाषण देते थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाषण देखे जायें तो आधे से ज्यादा भाषण उर्दू में होते थे।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिकते रज़ी) :
आप अपना प्वाइंट बता दीजिये।

اپ سبھا اڈھیکش شری سید
آپ اپنا پوائنٹ بتا دیجیے۔

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैं विनम्रता से सरकार से यह कह रहा था कि इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं है। जाली जैल मित्र जी को अभी कुछ और नहीं बनना है। जितना बना था, बन चुके, वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। उससे जाने कुछ नहीं बना है उनको। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसे सवालों पर गभीरता से सोचना चाहिये और उचित सम्मान के साथ इन बातों को रखना चाहिये। वस मैं इतना ही कहना चाहता था।

श्री जगदीश प्रताप साधु (उत्तर प्रदेश) : महोदय, क्या यह बहुत इस तरह से चलती रहेगी? इस बहस को बन्द किया जाये। इस बहस को बन्द करिये।

उपसभाध्यक्ष (सैयद सिकते रज़ी) :
जी, हाँ। वैसे भी अब लंच का वक्त हो रहा है। गुजराल जी, आप बोलिये।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL:
Sir, I will take a couple of minutes only to point out three things. One, of course, is that I belong to the diminishing community of those who have participated in the freedom struggle. I am also one of those who have sat in this House for long enough years

seeing these debates go on. I am also Chairman of a Committee which was called Gujral Committee on Urdu. When we examined Urdu, we did not examine Urdu. We examined the problems of Indian languages, their place in our life and their future. What was our basic presumption? The basic presumption of freedom struggle, the basic presumption of what put us together. And I do not agree with my friend that we had never broken in the past.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Not because of language, Sir.

SHRI INDER KUMAR GUJRAL: It may not be important. The unity of India is the primary source. I bow my head before our forefathers and those who framed the Constitution. They saw the vision of a diverse India. They saw the diversity of Indian languages. They knew that we have to find a common factor; and they found it. What did they find? They found two things. One, of course, is the equal status for all Indian languages. And because of historical reasons English has come in, it is there. So we also put it in the Eighth Schedule. Therefore, it has become a language of communication between us, rightly or wrongly. I am talking of history only. Now, we come to a different stage. That was how do we talk to each other? Therefore, the idea of a three-language formula was perceived. It is a misfortune—I am not blaming anybody—that the three-language formula has not been implemented honestly in any part of the country. This is a fact. This is also a fact that although we are moving towards creating a new type of Indianness, which is correct, we are trying to understand and find amongst ourselves the highest common factor. We are under different stresses and strains—the stresses caused by the unequal economic development, the stresses caused by all of us to get into the position of power and authority. It is correct, is nothing wrong in it. At the same time, we are trying to see the world changing. We cannot now shut our

doors and sit inside. I entirely endorse what my friend, the Minister, has said. I think this is the right policy to follow that all languages are available and all languages should be available. But, let us not become prisoners of the past in one sense that even if people talk of the moon, we shall talk in a language which does not spell that out. Let us try to build the language. Languages cannot be built overnight. People take centuries and centuries particularly to make a language modern and particularly to make a method of communication of the modern urges of the humanity. I, therefore, feel and appeal, if I may, with your permission, Sir,—and I do so, if you kindly give me some credit for being in that age group, which is slightly senior to others—I urge this debate must end on one note. And that note is we are Indians first, we are Indians last. All languages are ours and all shall prosper.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): The matter ends here. We adjourn for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at thirty-three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Miss Saroj Khaparde) in the Chair.

The payment of gratuity (Amendment) Bill, 1993.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Honourable Members before we take up Special Mentions, first we will take up the legislative business. Shri P. A. Sangma.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Madam Vice-Chairperson, I move;

“That the following amendments made by the Lok Sabha in the Payment of Gratuity (Amendment) Bill,

1994, be taken into consideration, namely:—

Enacting Formula

1. Page 1, line 1,—
for ‘Forty-fourth’ substitute ‘Forty-fifth’

Clause-1

2. Page 1, line 4,—
for ‘1993’ substitute ‘1994’

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. A. SANGMA: I move:

“That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to.”

The question was put and the motion was adopted.

Formation of Committee for Centenary Celebration of Acharya Vinoba Bhave

SPECIAL MENTIONS

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष जी, मैं इस विशेष उल्लेख के अन्तर्गत आज जिस बात की ओर सरकार और राष्ट्र का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उसमें मैं समझता हूँ कि पूरा सदन मेरे साथ रहेगा। महोदया, आचार्य विनोबा भावे की शताब्दी आ रही है और इसलिये मैं चाहता हूँ कि सरकार इस बात पर गंभीरता से सोचे कि आचार्य विनोबा भावे शताब्दी समारोह के लिये एक राष्ट्रीय समिति का गठन हो। राष्ट्रीय समिति का का ही गठन न हो बल्कि आचार्य विनोबा भावे ने जिन नैतिक मूल्यों, जिन कार्यों और जिन सर्वोदय सिद्धांतों के लिये कार्य किया है, उसके अनुसार सरकार प्रतिबद्ध रूप से कार्य करे। उपसभाध्यक्ष जी, राजनीति इस समय मूल्यहीन होती जा रही है। नैतिक मूल्यों का जिस तरह से हास हो रहा है, ऐसे समय में आचार्य विनोबा भावे की शताब्दी अगर रूप उन उद्देश्यों